

प्रेषक

डा०एम०सी० जोशी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

संवा में

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पावर कार्पोरेशन लि०,
देहरादून।

ऊर्जा विभाग,

देहरादून: दिनांक: 28, दिसम्बर, 2004

विषय:- ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु AREP योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004-05 में REC से प्राप्त ऋण के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या: 230/I/2004-06(1)/23/03, दिनांक 07 अप्रैल, 2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2004-05 में निम्नांकित विवरणानुसार विभिन्न जनपदों में उनके सम्मुख अंकित संख्या में ग्रामों/लोकों का विद्युतीकरण किये जाने हेतु व्यय वहन के लिये द्वितीय अग्रिम किरत के रूप में श्री राज्यपाल महोदय रु० 4,53,07,100/- (रु० चार करोड़ तिरपन लाख सत्त हजार एक सौ मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निर्वहन पर निम्न शर्तों के अधीन रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त धनराशि के सम्बन्ध में REC से ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु विभिन्न योजना कोड संख्या के रूप में स्वीकृत कुल ऋण एवं तदक्रम में अदमुक्त प्रथम अग्रिम किरत के समय इंगित REC की सभी शर्तों के प्राविधानानुसार उपलब्ध करायी जा रही है। REC से प्राप्त ऋण के सम्बन्ध में राज्य शासन, UPCL (लाभार्थी) एवं REC के मध्य हस्ताक्षर किये गये अनुबन्ध एवं हाईपोथिकेशन अनुबन्ध की सभी शर्तों का पालन UPCL द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि REC से स्वीकृत निम्नलिखित ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के सापेक्ष चिन्हित गांवों/लोकों के विद्युतीकरण एवं सम्बन्धित योजना में वर्णित विद्युतीकरण से सम्बन्धित कार्यों के व्यय वहन हेतु इस प्रकार किया जायेगा कि स्वीकृत योजना में उल्लिखित न्यूनतम समयावधि में विद्युतीकरण एवं वर्णित सभी कार्यों को शत प्रतिशत पूर्ण कर लिया जायेगा।

क०सं०	योजना कोड संख्या	कुल ऋण धनराशि (हजार रु० में)	जनपद
1-	58001100	7870.7	पौड़ी
	58001300	2799.6	
	58001800	8968.5	
2-	58001500	13902.5	टिहरी
	58001700	11765.8	
योग:-		45307.1	

९

✓

-2

4. उक्त जनपदों के सम्मुख ग्रामों/तोंकों की संख्या के सापेक्ष विद्युतीकरण हेतु योजना में चुने गये ग्रामों/तोंकों की सूची तत्काल शासन, सम्बन्धित जिलाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जायेगी तथा सम्बन्धित ग्राम के ग्राम प्रधान को भी सूचित किया जायेगा कि उनके किस गांव/तोंक का विद्युतीकरण इस योजना के अधीन कब तक किये जाने का लक्ष्य है, वहां न्यूनतम कितने विद्युत संयोजन किस श्रेणी के दिये जाने हैं एवं क्या-क्या अन्य कार्य सम्मिलित हैं। सम्बन्धित जिलाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को भी श्रेणीवार विद्युत संयोजन दिये जाने एवं किये जाने वाले कार्यों का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया जाय।
5. उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि० द्वारा प्रत्येक दशा में REC से सम्बन्धित योजनाओं के लिये ऋण स्वीकृति की सूचना सम्बन्धी REC के पत्रों के संलग्नक A व B (पूर्व में निर्गत शासनादेश के साथ संलग्न) में इंगित सभी शर्तों की शतप्रतिशत अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी। इसमें त्रुटि की दशा में उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि० एवं उनके सम्बन्धित अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
6. UPCL द्वारा योजना के अधीन विद्युतीकरण का कार्य समय से पूर्ण कर REC से तत्काल एवं समय से प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत कर सम्पूर्ण योजना के लिये स्वीकृत ऋण के समतुल्य धनराशि की समझ से प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की जायेगी एवं जहां सम्बन्धित कार्यों को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी, उसे UPCL द्वारा अपने श्रोतों से वहन किया जायेगा।
7. ग्रामों/तोंकों के विद्युतीकरण/योजना में वर्णित सुविधाओं के सृजन के पश्चात् सम्बन्धित ग्राम प्रधान से नियत प्रमाण पत्र प्राप्त कर REC व शासन को प्रेषित किया जायेगा, जैसा कि योजना की शर्तों में वर्णित है। साथ ही विद्युतीकरण उपरान्त ग्रामों/तोंकों की सूची समयान्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराई जायेगी, जो अपने स्तर से इसका सत्यापन कर सकेंगे। जिलाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा उक्तानुसार सत्यापन में पाई गई किसी त्रुटि या कमी तथा सत्यापन का विवरण UPCL एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उल्लेखनीय है कि सूची का प्रकाशन 20 सूत्रीय कार्यक्रम का अग्रिम अंग है तथा उसमें शिथिलता मान्य नहीं है।
8. REC द्वारा स्वीकृत योजना में सम्बन्धित ग्रामों/तोंकों के विद्युतीकरण के साथ-साथ योजना में इंगित निर्धारित संख्या में विद्युत संयोजनों/भार की प्राप्ति, जैसा कि पूर्व निर्गत शासनादेश के संलग्नक में वर्णित है, भी अवश्य सुनिश्चित की जायेगी।
9. नियत अवधि में कार्य पूर्ण न होने पर ब्याज की अतिरिक्त देयता की जिम्मेदारी UPCL/UPCL के सम्बन्धित अधिकारियों की होगी।
10. ऋण एवं ब्याज की समझ से वापसी उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि० द्वारा शासन को इस प्रकार सुनिश्चित की जायेगी कि शासन द्वारा ऋण एवं ब्याज की वापसी आर.ई.सी. को समय से की जा सके। मोरटोरियम की अवधि में देय ब्याज का समय से भुगतान भी उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि० द्वारा शासन को उक्तानुसार सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि० द्वारा भुगतान के विवरण साक्ष्य सहित शासन को यथासमय उपलब्ध कराये जायेंगे और ब्याज की धनराशि संघित निधि में जमा कराने के उपरान्त ही राज्य सरकार द्वारा आर.ई.सी. का ब्याज वापस किया जायेगा।
11. नियत अवधि पर भुगतान/वापसी न करने पर 2.75 प्रतिशत छद्मवृद्धि ब्याज दण्ड के रूप में अतिरिक्त देय होगा तथा 6 माह से अधिक भुगतान/वापसी में षूक की दशा में योजना का विशेष स्वरूप समाप्त हो जायेगा, जिस दशा में ऋण पर सामान्य ब्याज (ऋण स्वीकृति के समय प्रचलित) लगेगा। अतः उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि० द्वारा प्रत्येक दशा में योजना का संपादन/क्रियान्वयन निर्धारित प्रक्रिया एवं शर्तों के अनुसार समय से करते हुये नियत तिथि तक किस्त व ब्याज की राशि प्रत्येक दशा में भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. योजना में इस किस्त आहरण के बाद यदि कोई अगला प्रतिपूर्ति दावा नियत अपरि में REC को प्रस्तुत नहीं किया जायेगा तो किरत में अवमुक्त सम्पूर्ण ऋण की राशि को ब्याज/दण्ड ब्याज सहित REC को वापस किया जायेगा।
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का निर्धारित समय में उपबोध कर उस धनराशि से योजनावार कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार व राज्य सरकार को उपलब्ध करा दिया जायेगा, ताकि आगामी किस्त प्राप्त होने में विलम्ब न हो।
14. उक्त स्वीकृत राशि पर आर०ई०सी० के पत्र सं० REC/FIN/LOAN/CIU/2004-05/03, दिनांक 14.12.2004 में धनराशि अवमुक्ति तिथि के अनुसार ब्याज की देयता 14 दिसम्बर, 2004 से आगणित होगी।
15. किस्तों एवं ब्याज की वापसी नियत तिथि से पूर्व अवश्य कर दिया जाय एवं इस हेतु नोटिस/सूचना का इन्तजार न किया जाय। धनराशि सीधे REC को भुगतान करते हुये शासन को सूचना ससमय दी जाय।
16. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण योजना पर अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि० के हस्ताक्षर एवं जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर उपरान्त कोषागार में प्रस्तुत कर किया जायेगा।
17. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 के आद्य-व्ययक के अनुदान संख्या 21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 6801-विजली परियोजनाओं के लिये कर्ज-05-परिषण एवं वितरण-आयोजनागत-190-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों व अन्य उपक्रमों में निवेश-आयोजनागत-01-केंद्रीय आयोजनागत/केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-04-उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि० को REC से ऋण-30-निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अज्ञातकीय सं०- 2188/वि०अनु०-3/2004, दिनांक 27 दिसम्बर, 2004 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

सलग्नक-यथाका।

भवदीय,

(डा०एम०सी० जोशी)
अपर सचिव

संख्या: 857/1/2004-06(1)/23/03, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तरांचल।
- 2- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को मा० मन्त्र्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
- 3- निजी सचिव, ऊर्जा राज्य मंत्री, उत्तरांचल शासन को मा० राज्य मंत्री के संज्ञान में लाने हेतु।
- 4- जिलाधिकारी, देहरादून/समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 6- सचिव, उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग, उत्तरांचल, देहरादून।
- 7- सचिव, नियोजन विभाग।
- 8- वित्त अनुभाग-3।
- 9- प्रभारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 10- गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

21/3

(डा०एम०सी० जोशी)

अपर सचिव